आज़ादी का
अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 28.08.2023 से 03.09.2023)

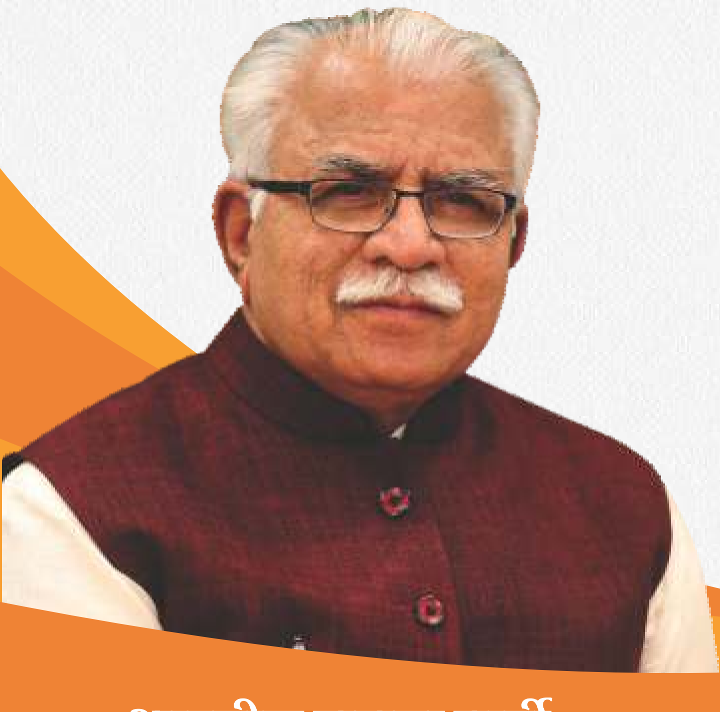

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

अंतरराष्ट्रीय एथलीट नीरज चोपड़ की ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देना

(दिनांक 28.08.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंतरराष्ट्रीय एथलीट नीरज चोपड़ा द्वारा विश्व एथलेटिक्स चौम्पियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। यहां हरियाणा विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान सदन को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य और देश दोनों को फिर से गौरवान्वित करने के सुनहरा अवसर दिया है।

नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चौंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले एथलीट बने हैं। उन्होंने नीरज चोपड़ा के परिवार, कोचों और सभी खेल प्रेमियों को भी बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नीरज चोपड़ा के निरंतर प्रयासों से वैश्विक मंच पर हरियाणा और देश को

और अधिक जीत मिलेगी। उन्होंने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए हरियाणा सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया और आश्वस्त किया कि राज्य खेलों को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा, जिससे एथलीटों को अपने हुनर का प्रदर्शन करने और सफल होने के लिए एक मंच सुनिश्चित होगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

विधानसभा मानसून सत्र

(दिनांक 28.08.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विभिन्न विधेयक पर चर्चा की जिसके अनुसार... प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है। हालांकि, योजना के नियम व दिशा निर्देशों के अनुसार, वे जिन्होंने ऋण लिया हुआ है, वे इस योजना के तहत पंजीकृत होने की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले तक योजना का विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन 7 दिन पहले तक यदि किसान, जिसने ऋण लिया हो, उसने योजना से ऑप्ट–आउट नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में ऋणी किसान का प्रीमियम काटा जाता है।

ग्रुप ए और बी पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा

माननीय मुख्यमंत्री जी एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्रुप ए और बी पदों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण नीति लागू करेगी। इस निर्णय

का उद्देश्य उच्च–स्तरीय सरकारी पदों पर सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाना है। पहले आरक्षण ग्रुप सी और डी तक सीमित था, ग्रुप ए और बी पदों को बिना किसी आरक्षण प्रावधान के छोड़ दिया गया था।

इस आरक्षण व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार रोस्टर प्रणाली बनाने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जो निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

निकाय चुनावों में बीसी (ए) को आरक्षण का दिया जाएगा लाभ

स्थानीय निकायों में वार्डबंदी का कार्य हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किया जा रहा है। वार्डबंदी के लिए दो आधार माने गए हैं। निकायों में वार्डों की संख्या निमित करने के लिए फैमिली इनफार्मेशन डाटा रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) या मतदाताओं की 140 प्रतिशतता अनुसार प्राप्त जनसंख्या, दोनों में से जो भी अधिक हो, को आधार माना जायेगा। इसके अलावा, वार्डों में जनसंख्या की भिन्नता को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया है। पंचायतों के बाद अब निकाय चुनावों में भी बीसी (ए) को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) और हरियाणा नगर पालिका (संशोधन)

हरियाणा नगर निगम (संशोधन), अध्यादेश में जनसंख्या के लिए एफआईडीआर, जोकि एक रिपॉजिटरी है, जिसे परिवार पहचान पत्र अधिनियम के तहत तैयार किया है। आरक्षण के संबंध में जहाँ तक बात है, उसके लिए सरकार ने हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग बनाया जिसने कुछ सिफारिशें की। जनसंख्या के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों के अनुरूप जिले में एक निकाय में बीसी (ए) जनसँख्या की

प्रतिशतता का 50 प्रतिशत आरक्षित की जाएगी। यदि 20 सीटें हैं तो 5 प्रतिशत जनसंख्या के हिसाब से बीसी (ए) के लिए एक सीट आरक्षित होगी। यहाँ तक कि बीसी (ए) जनसंख्या 2 प्रतिशत होने पर भी हमने कम से कम एक सीट आरक्षित रखना सुनिश्चित किया है।

पहले चेयरमैन का चुनाव पार्षद ही करते थे, इसलिए हमने 2 सीटें आरक्षित की हुई थी, ताकि उनमें से चुनाव किया जा सके। लेकिन अब चेयरमैन का चुनाव सीधा होता है, इसलिए बीसी (ए) जनसंख्या 2 प्रतिशत होने पर भी हमने कम से कम एक सीट आरक्षित रखना सुनिश्चित किया है। हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में 6–7 सीटें ऐसी बच गई, जहाँ पर वार्ड बीसी (ए) का था, लेकिन बीसी (ए) का एक भी मतदाता नहीं था, इसलिए हमें उन सीटों पर उप चुनाव करवाने पड़े, जिसमें दूसरे वार्डों के लोगों ने चुनाव लड़ना पड़ा।

ग्रुप सी व डी भर्ती के लिए नई नीति

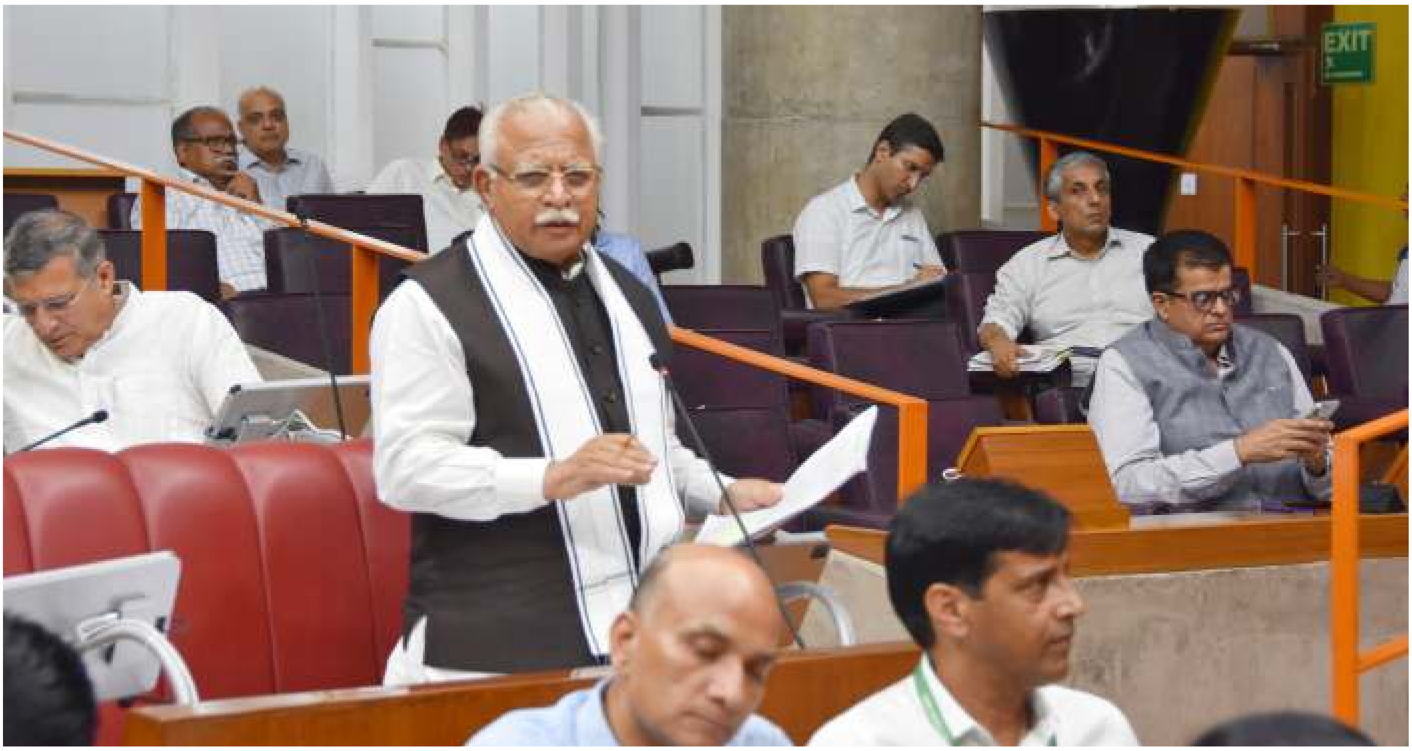

साप्ताहिक सूचना पत्र

मानसून सत्र में प्रश्न काल के दौरान एक सदस्य द्वारा लगाए गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सरकारी भर्तियों में पहले बहुत लंबा समय लगता था, पदों की संख्या भी बहुत अधिक होती थी और पदों की श्रेणियां भी अधिक बनती थी। इसलिए इस प्रक्रिया को स्पीड अप करने के लिए सरकार ने ग्रुप सी व डी भर्ती के लिए नई नीति बनाई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नई नीति के तहत ग्रुप डी पदों का एक कैडर बनाया और परीक्षा ली जाएगी। यदि उम्मीदवार चयनित होने के कुछ समय बाद अपना विभाग बदलना भी चाहते हैं तो वे वरिष्ठता के आधार पर बदल सकते हैं। नई नीति के तहत सीईटी परीक्षा के लिए ग्रुप सी पदों की लगभग 35 हजार पदों को विज्ञापित किया गया। राज्य सरकार ने एक सामान्य पात्रता–परीक्षा ली। विभागों में पद कम या ज्यादा हैं, इसलिए पारदर्शी और योग्य उम्मीदवार का चयन करने हेतु सीईटी परीक्षा–1 पास करने वाले उम्मीदवारों में से 4 गुणा उम्मीदवारों को बुलाया गया है। ग्रुप 56– 57 की अभी परीक्षा हुई है। जिसमें प्रश्नों के रिपीट होने का भी एक मामला सामने आया। वर्तमान में मामला न्यायालय में है।

जिन उम्मीदवारों को सीईटी परीक्षा में आयु सीमा में छूट प्रदान की गई थी, उनके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 30 अप्रैल, 2023 को निर्णय लिया कि जो उम्मीदवार सीईटी स्तर–1 परीक्षा में पात्र थे, लेकिन अब अधिक उम्र के हो गए हैं, उन्हें स्तर–प्प् के लिए अनंतिम रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, यदि पिछली परीक्षाओं के रद्द होने के कारण, कोई उम्मीदवार हरियाणा सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 52 पार कर चुका है, तो उसे भी अनंतिम रूप से आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। यदि वे चयनित हो जाते हैं तो उस संदर्भ में सरकार निर्णय लेगी।

शून्यकाल के दौरान विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा उठाये गए एक मुद्दे पर सदन में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता ही देखती है कि उसे

क्या करना है और क्या नहीं। उन्होंने कहा है कि जनता के प्रति जवाबदेही और जिम्मेवारी हमारी है। सरकार कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल के दौरान महिलाओं व अनुसूचित जाति के लोगों पर हुए अत्याचारों व अन्य कारनामों को लेकर जनता के बीच जाएगी और जनता ही फैसला करेगी कि क्या सही है और क्या गलत?

इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा परिवार पहचान पत्र पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कहा कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और अन्य सेवाओं को लाभार्थी के घर द्वार पर पहुंचाना है।

पीपीपी आधार द्वारा निर्मित डिजिटल बुनियादी ढांचे और सिद्धांतों से लिया गया है। हालांकि इसकी प्रदायगी में यह आधार से कई गुना अधिक जटिल है। आधार में मुख्य रूप से यूनीक पहचान की जानकारी होती है, जबकि पीपीपी में

आधार के रूप में विशिष्ट पहचान की जानकारी के अलावा सामाजिक–आर्थिक जानकारी भी होती है। आधार पहचान के अलावा किसी भी डेटा को सत्यापित नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर आधार में जन्मतिथि सत्यापित नहीं होती।

दूसरी और पीपीपी में उपलब्ध प्रत्येक जानकारी फील्ड को विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। उन्होंने कहा कि आधार को बड़े पैमाने पर तैयार करने और योजनाओं के साथ एकीकरण करने में 6 साल से अधिक का समय लगा, जबकि पीपीपी, बीच में कोरोना वायरस महामारी के बावजूद 2 साल में तैयार कर लिया गया।

पीपीपी में एक परिवार के सभी व्यक्तियों के डेटा तत्वों का संकलन होता है, जो योजनाओं और सेवाओं के लिए पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा अपेक्षित है। पीपीपी में पारिवारिक रिश्ते भी उल्लिखित होते हैं और प्रत्येक परिवार को 8 अंको की पारिवारिक आईडी प्रदान

की जाती है। पारिवारिक संरचना को भी हर समय अपडेटेड रखा और अद्यतन किया जाता है, जिसमें जन्म, मृत्यु या विवाह के कारण होने वाले परिवर्तन, जहाँ तक संभव हो इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वचालित रूप से, एकत्रित और अद्यतन किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान संख्या से कई योजनाओं और सेवाओं के लिए शपथ पत्र या दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदक को पहले एक आवेदन के साथ एक हलफनामा जमा करना पड़ता था, जिसे नंबरदार, पटवारी, कानूनगो द्वारा सत्यापित किया जाता था और उसके बाद भौतिक पद्धति में तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता था। उन्होंने कहा कि अप्रैल, 2022 में पीपीपी के माध्यम से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को सक्रिय

रूप से जारी करने की शुरुआत के बाद आवेदक को ऑनलाइन ढंग से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है और उसके बाद एससी प्रमाणपत्र प्रिंट करना होता है। यह योजना शुरू होने के बाद 25 अगस्त, 2023 तक 6.96 लाख से अधिक प्रमाणपत्र जारी किये जा चुके है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लाभ को सक्रिय रूप से पीपीपी से जोड़ा गया है। सत्यापन प्रक्रिया में 59 से 70 आयु वर्ग के सभी लोगों की पहचान की जा रही है और उन लोगों की भी पहचान की जा रही है जो पिछली प्रक्रिया में छूट गए थे और भत्ता शुरू करने के लिए उनकी सहमति ली जा रही है। यह प्रक्रिया सितंबर 2023 तक पूरी होने की संभावना है। हालांकि, जब भी किसी लाभार्थी की पहचान की जाती है तो सामग्री की सहमति और पेंशन शुरू करने के लिए

डेटा को सामाजिक न्याय, अधिकारिता कल्याण और एससी/ बीसी विभाग और अंत्योदय (सेवा) विभाग को भेज दिया जाता है। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त, 2023 तक 1,03,828 लाभार्थियों को सक्रिय पद्धति से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त हुआ है और हाल ही में अन्य 90,000 लाभार्थियों का डेटा सहमति लेने के लिए पीपीपी द्वारा सेवा को भेज दिया गया है। परिवारों द्वारा पीपीपी में स्व घोषित डेटा के कारण 63,353 लाभार्थियों का वृद्धावस्था सम्मान भत्ता रोक दिया गया। सत्यापन के बाद 44,050 लाभार्थियों को भत्ता बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चालू शैक्षणिक वर्ष 2023–24 में पीपीपी डेटा के आधार पर निजी और सरकारी स्कूलों में 3.52 लाख नए प्रवेश हुए हैं। इसी प्रकार उच्च शिक्षा विभाग के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से पीपीपी डेटा का उपयोग करके कॉलेजों में 1.28 लाख दाखिले किए गए है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में प्रवेश अभी भी चल रहा है और अब तक कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर आईटीआई में प्रवेश के

लिए पीपीपी का उपयोग करते हुए 1.01 लाख पंजीकरण हुए हैं, जिनमें से 61,405 का दाखिला हो चुका है। वर्ष 1966 में हरियाणा गठन के बाद पहली बार तीन विधायकों असीम गोयल, जोगीराम सिहाग व अमित सिहाग को सदन की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारिता व लोकहित के मुद्दे उठाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में पुरस्कृत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता व माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कारों की परम्परा शुरू की गई। इससे पहले दो विधायकों को ही पुरस्कृत किया जाता था। इस सत्र से तीन विधायकों को पुरस्कार देने की एक नई परिपाटी की शुरुआत की गई है। पुरस्कार स्वरूप शॉल, प्रशस्ति पत्र, विधानसभा का स्मृति चिन्ह व क्रमशः एक लाख 1 हजार रुपये, 71 हजार रुपये और 51 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए यह एक यादगार अवसर होता है जब सदन में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में स्मरण किया जाता है। इससे अन्य सदस्यों के लिए भी एक प्रेरणा मिलती है।

ग्रामीण चौकीदारों को तोहफा

(दिनांक 30.08.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैथल, कुरूक्षेत्र, पानीपत, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, करनाल सहित राज्य भर से आए ग्रामीण चौकीदारों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रक्षाबंधन के पावन अवसर पर ग्रामीण चौकीदारों को नायाब तोहफा देते हुए कई अहम घोषणा की है। अब चौकीदारों को 11000 रुपए मानदेय व शेयर 4000 रुपए वर्दी भत्ता एवं हर 5 साल के बाद साइकिल मिलेगी। इसके अलावा चौकीदारों को 1000 रुपए लाठी एवं बैटरी के लिए सालाना मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण चौकीदार गांव की ईकाई में अहम कड़ी होता है। चौकीदार से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के अलावा अब शादी पंजीकरण कार्य में भी पूर्ण सहयोग लिया जाता है। उन्होंने कहा कि मृत्यु पंजीकरण की राशि 300 रुपए की बजाय 400 रुपए हर माह मिलेगी। उन्होंने कहा कि चौकीदारों के मानदेय के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की

जाएगी। इसके लिए चौकीदार ग्राम सचिवालय एवं पंचायत घर में ऑनलाईन बटन दबाकर अपनी हाजिरी सुनिश्चित करेंगे ताकि उन्हें मानदेय हर माह समय पर मिल सके।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चौकीदारों को बढ़ा हुआ मानदेय अक्टूबर 2023 से लागू होगा और नवम्बर माह के मानदेय में मिलेगा। इस पर चौकीदार संगठनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने ग्रामीण चौकीदारों के लिए कई घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण चौकीदारों को भी आकस्मिक मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की राशि का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण चौकीदारों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तर्ज पर सेवानिवृति के दौरान एकमुश्त 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा चौकीदारों को ईपीएफ योजना के तहत 12 प्रतिशत स्वयं वहन करना होता है और 12 प्रतिशत हिस्सा सरकार की ओर से जमा

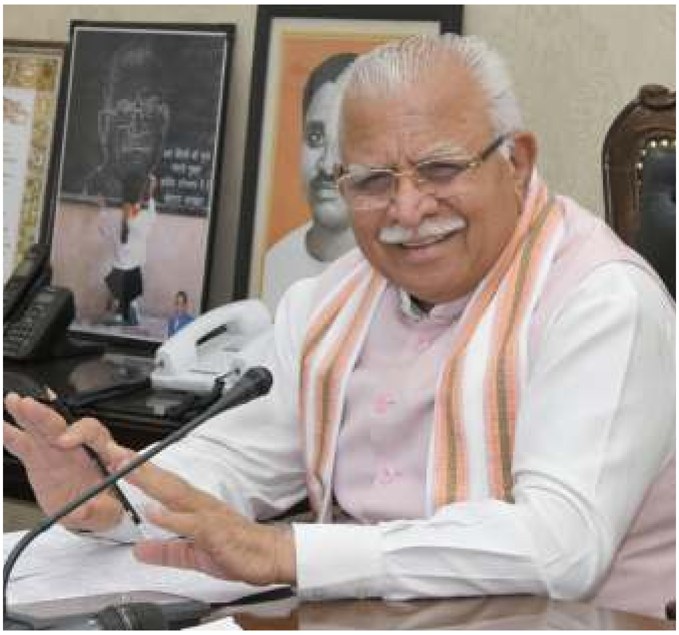

करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो गांव नगर निगम में आ जाते हैं उनके ग्रामीण चौकीदारों को योग्यता अनुसार अन्य पदों पर समायोजित किया जाएगा। यह निर्णय चौकीदारों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। ग्रामीण चौकीदार नगर निगम में उनकी योग्यता अनुसार पदों पर समायोजित किए जाएगें। इसके अलावा मृत्यु रजिस्ट्रेशन में मिलने वाली राशि 300 से बढ़ाकर 400 रुपए कर दी गई है। इसके लिए ग्रामीण चौकीदार कॉमन सर्विस सेंटर पोर्टल पर अपलोड करवाएं। यह राशि उन्हें हर माह प्रदान की जाएगी।

सीएम विंडो पर आई एक शिकायत पर नायब तहसीलदार को निलंबित करना

(दिनांक 31.08.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम विंडो पर आई शिकायत पर सही ढंग से कार्यवाही न करने और काम में कोताही बरतने के मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला हिसार के खेडी जालब के नायब तहसीलदार सुरेश कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

साथ ही, उनके विरुद्ध हरियाणा सर्विस रूल, 2016 के नियम–7 के तहत विभागीय कार्यवाही करने के भी आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिकायत निवारण सेल द्वारा 2 फरवरी, 2023 को नायब तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि कानूनगो को शीघ्र नक्शा प्रस्तुत करने बारे कहा जाये और मामले में आगामी कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट अपलोड की जाये।

लेकिन नायब तहसीलदार द्वारा सीएम ग्रीवांसीज सैल के निर्देशों को नजरअंदाज कर मामले में बिना कोई कार्यवाही किये 16 अप्रैल, 2023 को पुरानी रिपोर्ट ही पुनः पोर्टल पर अपलोड कर दी।

करनाल में ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन का शुभारंभ

(दिनांक 01.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज शुक्रवार को साइक्लोथॉन रैली को हरी झंडी दिखाने से पूर्व भारी संख्या में पहुंचे युवाओं को संबोधित कर कहा कि हरियाणा 3 लाख युवाओं की भागीदारी के साथ मध्य प्रदेश के इस रिकॉर्ड को तोड़कर साइक्लोथॉन रैली में विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि दानवीर कर्ण की नगरी करनाल से नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम की शुरूआत की जा रही है, जोकि प्रदेश के जिलों से होते हुए 25 सितम्बर को सायं के समय करनाल में ही युवाओं की एक बहुत बड़ी रैली के साथ समाप्त होगी। ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत निकाली जा रही साइक्लोथॉन रैली के संदेश की गूंज देश के कोने–कोने तक जाएगी और युवा पीढ़ी

साप्ताहिक सूचना पत्र

का जीवन सुरक्षित रहेगा। इस से पहले उन्होंने साइक्लोथॉन रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मध्य प्रदेश द्वारा साइकिल रैली में करीब 37 हजार प्रतिभागियों के साथ रिकॉर्ड बनाया गया है। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करते हुए कहा कि करनाल में हर मंगलवार कार–फ्री डे रहेगा। सभी सरकारी अधिकारी साइकिल से ही यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं भी अगर करनाल आऊंगा तो मंगलवार को साइकिल से ही यात्रा करूंगा। उन्होंने कहा कि साइक्लोथॉन रैली भी एक योगा है। इससे शरीर का संतुलन बनता है और शारीरिक विकास होता है। साइक्लोथॉन रैली में भाग लेने वाले युवाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्साहवर्धन किया और कहा कि इस रैली में जहां लड़के भाग ले रहे हैं, वहीं बेटियां भी पीछे नहीं हैं। इतना ही नहीं रक्षा बंधन के मौके पर ग्रामीण चौकीदारों के वेतन में बढ़ोतरी की जाने की खुशी में साइक्लोथॉन रैली में

ग्रामीण चौकीदारों ने भी बड़े उत्साह के साथ भाग लिया है। उन्होंने साइक्लोथॉन रैली को झंडी दिखाने से पूर्व युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत निकाली गई मेगा साइक्लोथॉन रैली के सफल आयोजन में खेल विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ–साथ स्थानीय प्रशासन का सराहनीय योगदान रहा। वहीं दूसरी ओर सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने साइक्लोथॉन रैली को झंडी दिखाने के उपरांत स्वयं भी युवाओं के साथ रैली में साईकिल चलाई। मेगा साइक्लोथॉन रैली में अधिक से अधिक संख्या में प्रदेश के युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी साईकिल पर सवार होकर साइक्लोथॉन रैली में शामिल हुए और युवाओं से भारत माता की जय तथा ड्रग फ्री हरियाणा के नारों से आकाश को गूंजयमान किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति आगे बढ़ो और नशे जैसी बुराई से दूर रहो।

एंटी करप्शन ब्यूरो की भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध मुहिम

(दिनांक 01.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति पर चलते हुए हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध मुहिम तेज कर दी है । इसी कड़ी में ब्यूरो ने रेवाड़ी जिले की खोल पुलिस चौकी में तैनात मुख्य सिपाही को 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि इसी प्रकार एक अन्य मामले में अवैध शराब बेचने के झूठे मामले में दर्ज एक शिकायत से नाम हटवाने के एवज में 10 हजार रुपये की मांग करने के मामले में बलदेव नगर अम्बाला शहर के मुख्य सिपाही जसबीर सिंह को भी गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार, पुलिस स्टेशन सदर हिसार के मुख्य सिपाही राकेश कुमार को भी सत्य नगर के सुरेश कुमार की शिकायत पर 10 हजार रुपये की रिश्वत की मांग पर गिरफ्तार किया है।

फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति बैठक

(दिनांक 02.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज शनिवार को फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में नगर निगम से सम्बंधित परिवादों की सुनवाई उपरांत आमजन को जानकारी दे कर कहा कि पूरे फरीदाबाद शहरी क्षेत्र को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा।

नगर निगम द्वारा आईआईटी दिल्ली/रुड़की के माध्यम से सर्वे कराते हुए व्यवस्थित ढंग से फरीदाबाद मेट्रोपोलिटन डेवेलपमेंट अथॉरिटी के साथ आधारभूत ढांचागत विकास करने के लिए जनहित में दिशा–निर्देश दिए गए हैं, ताकि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष कुल 14 परिवाद रखे गए, जिनमें से 12 परिवाद का निपटान मौके पर

किया गया।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आईआईटी टीम के सहयोग से नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रक्चर व लेवलिंग की जांच की जाएगी और जहां सुधार किया जाना है या विकास योजनाओं के तहत नया स्वरूप दिया जाना है, इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। सिस्टम के साथ जन सेवा के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की रूपरेखा बनाते हुए सड़क निर्माण, जल निकासी सहित अन्य व्यवस्थापूर्ण प्रबन्ध मास्टर प्लान के तहत होंगे। उन्होंने कहा कि सीवरेज सिस्टम, सड़क तंत्र सहित पेयजल व्यवस्था के अनुरूप डिजाइन फाइनल करते हुए मास्टर प्लान को क्रियान्वित किया जाएगा।

बैठक में जल प्रबंधन पर पूरा फोकस रखने के निर्देश भी दिए गए और आमजन से अपील की गई कि जल संरक्षण पर ध्यान देना समय की जरूरत है।

बैठक में नगर निगम से जुड़े विभिन्न परिवादों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि किसी भी रूप से नगर निगम अधिकारी व कर्मचारियों की ओर से गड़बड़ सहन नहीं कि जाएगी। जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन ईमानदारी से करें। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध निर्माण किसी भी रूप से सहन नहीं होगा और जहां कहीं कोई अवैध निर्माण अथवा अतिक्रमण करता है तो तुरन्त प्रभाव से एक्शन लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज श्रीहरिकोटा से आदित्य–एल–1 की सफल लॉन्चिंग पर वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार चन्द्रयान–3 की सफल लैंडिंग ने देश का मान बढ़ाया है ठीक उसी प्रकार अब आदित्य एल–1 की लॉन्चिंग के साथ सफल परीक्षण के लिए वैज्ञानिक अग्रिम बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

फरीदाबाद में 11 विकास परियोजनाओं का शिलान्याय करना

(दिनांक 02.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज जिला फरीदाबाद के नागरिकों को करीब 93 करोड़ रुपये से ज्यादा की 11 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए मनोहर सौगात दी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की 66 करोड़ 50 लाख रुपये की छरू सड़क परियोजनाओं, 19 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से बनने वाले चार स्कूल भवन और 6 करोड़ 99 लाख 75 हजार रुपए की लागत से एचएसवीपी के सेक्टर 48 में बनने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने

साप्ताहिक सूचना पत्र

कहा कि सड़क तंत्र की मजबूती के साथ ही बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदेश के बच्चों को दिया जा रहा है। युवा शक्ति को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के साथ उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित किये जा रहे हैं।

उन्होंने फरीदाबाद में शिलान्यास कार्यक्रम के अंतर्गत 7.25 किलो मीटर लंबे फरीदाबाद–मंगरोला सड़क के पुनःनिर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जिस पर कुल 17 करोड़ 51 लाख 58 हजार की राशि खर्च की जाएगी। इसी प्रकार चार मार्गीय 7.99 किमी लंबी सड़क के निर्माण पर 27 करोड़ 15 लाख 20 हजार की राशि खर्च की जाएगी।

इसके अलावा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अटाली से अरवा सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इसी प्रकार 2.76 किमी लंबे सीकरी से पियाला सड़क मार्ग के सुदृढ़ीकरण पर 1 करोड़ 39 लाख 2 हजार रुपए की राशि से खर्च होगी। उन्होंने एनआईटी –1 फरीदाबाद के राजकीय उच्च विद्यालय के भवन का भी शिलान्यास किया। लगभग 3.78 लाख रुपये की राशि से इस विद्यालय में क्लास रूम, विज्ञान प्रयोग शाला प्राचार्य कक्ष, स्टाफ रूम, स्थापना शाखा, शौचालय और रैंप का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने राजकीय माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बडौली में 3 करोड़ 60 लाख की लागत से बनने वाले नए भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।

इसी प्रकार शहीद लेफ्टिनेंट राजेश थापा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण कार्य पर 7 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से स्कूल में कमरे, प्रयोग शाला सहित अन्य जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वहीं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तिगांव में 4 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से स्कूल भवन सहित विज्ञान प्रयोग शाला का निर्माण कराया जाएगा।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा

साप्ताहिक सूचना पत्र

सेक्टर 48 में बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस भवन के निर्माण पर 6 करोड़ 99 लाख 75 हजार रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस सामुदायिक भवन में टेबल टेनिस टेनिस, जिम, बैडमिंटन हाल सहित अन्य जरूरी सुविधाएं आम जन को मिलेंगी। आगामी 18 महीने में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

18 पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीकी देशों के राजदूतों और दूतावास अधिकारियों के रात्रिभोज की मेजबानी

(दिनांक 02.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने गत देर सायं नई दिल्ली में पूर्वी और दक्षिण अफ्रीकी देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों और दूतावास के अधिकारियों के लिए आयोजित रात्रिभोज कार्यक्रम की मेजबानी की।

इस रात्रिभोज कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों व पदाधिकारियों और हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। रात्रिभोज कार्यक्रम में तंजानिया, केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, दक्षिण सूडान, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, मलावी, सेशेल्स, मॉरीशस, जाम्बिया, बोत्सवाना, नामीबिया, मेडागास्कर, जिम्बाब्वे के राजदूत, उच्चायुक्त और दूतावासों के अधिकारी पहुंचे।

इस रात्रिभोज में विदेश मंत्रालय और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के

साथ–साथ अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मौजूद महिला राजदूतों और उच्चायुक्तों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी बांधी।

इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा और पूर्वी तथा दक्षिण अफ्रीकी देशों के बीचराजनयिक संबंधों को मजबूत करने, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक आदान–प्रदान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि न केवल राजनयिक संबंध, बल्कि दिल से दिल का संबंध स्थापित करने के लक्ष्य पर हमें बल देना है।

न्होंने कहा कि हरियाणा ने विदेशी सहयोग विभाग (एफसीडी) के माध्यम से अपनी वैश्विक उपस्थिति स्थापित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एफसीडी को अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दुनिया भर में हरियाणवी प्रवासी का समर्थन करने का काम सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि एफसीडी ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से 28–29 अक्टूबर, 2021 को चंडीगढ़ में हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव सीरीज़ 1

का आयोजन किया, जिसमें इरिट्रिया, इथियोपिया, घाना, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, मोज़ाम्बिक, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, युगांडा और ज़िम्बाब्वे सहित 12 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि एक साथ शामिल हुए। यह अफ्रीकी देशों के साथ जुड़ने का एक उल्लेखनीय प्रयास है और कॉन्क्लेव के बाद के वर्षों में, एफसीडी ने अपने प्रयास जारी रखे। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में आर्थिक सम्पर्क सचिव श्री दाम्मू रवि ने आपसी विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए अफ्रीकी देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। इस कार्यक्रम में विदेश सहयोग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजा शेखर वुंडरू ने अतिथियों का स्वागत किया। रात्रिभोज कार्यक्रम में हरियाणा ने अपने सांस्कृतिक और औद्योगिक कौशल का प्रतीक–जगाधरी, यमुनानगर का धातु बर्तन क्लस्टर भी प्रदर्शित किया।

एफआईए के अध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल व उद्योगपति केसी लखानी के पुत्र के निधन पर शोक व्यक्त करना

(दिनांक 02.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने शनिवार को फरीदाबाद में एफआईए के अध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल व उद्योगपति केसी लखानी के पुत्र गुजन लखानी के निधन पर उनके निवास स्थानों पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। दोनों हस्तियों के निधन से समाज को बड़ी क्षति हुई है। गत 15 जुलाई को उद्योगपति व एफआईए के अध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल का निधन हो गया था। वहीं 23 अगस्त को उद्योगपति केसी लखानी के पुत्र गुजन लखानी का निधन हो हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद के सेक्टर–21 ए स्थित दिवंगत नरेंद्र अग्रवाल के घर पहुंचे और दिवंगत के परिजनों से मुलाकात करके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। इसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी सेक्टर–14 स्थित उद्योगपति श्री केसी लखानी के सपुत्र दिवंगत गुजन लखानी के आवास पर पहुंचे और उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

साप्ताहिक सूचना पत्र

डॉ सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र का लोकार्पण करना

(दिनांक 02.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज शनिवार को फरीदाबाद में भारत विकास परिषद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित डॉ सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र का लोकार्पण किया।

लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए इस डायग्नोस्टिक एवं डे केयर अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना पुण्य का कार्य है।

भारत विकास ट्रस्ट द्वारा संचालित डॉ सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में समस्त चिकित्सक गरीबों के प्रति सेवा भाव रखते हुए बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की 51 सदस्य टीम आरोग्य केंद्र का सुचारू रूप से संचालन कर रही है, जिसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और स्वस्थ बने, उन्हें ऐसे संस्थानों में इलाज के लिए नहीं आना पड़े। साथ ही उन्होंने आमजन से नियमित योगाभ्यास का आह्वान किया और कहा कि नियमित योगासन करें और दौड़ लगाएं व साइक्लिंग करें।

आरोग्य केंद्र का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि इस आधुनिक अस्पताल में डायलिसिस सेंटर, नेत्र जांच, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, जर्नल फिजिशियन, छाती एवं टीबी रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा जरूरी चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिसर में स्थापित ऑपरेशन थिएटर, जनरल वार्ड, आधुनिक प्रयोगशाला सहित अन्य सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों व ट्रस्ट के सदस्यों से बातचीत भी की।

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद

(दिनांक 02.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज फरीदाबाद से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद कर कहा कि वर्तमान राज्य सरकार अंत्योदय के हक की सरकार है। अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब का हक न तो कोई और ले सकता है और न ही हम किसी और को लेने देंगे। इसी दिशा में गरीब परिवारों के उत्थान के लिए हमने प्रदेश में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से 1 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवारों की वार्षिक आय कम से कम 1 लाख 80 हजार रुपये करने का बीड़ा उठाया है। अब तक प्रदेश में लगभग 50 हजार लोगों को मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत लगाये गये अंत्योदय मेलों में मदद मिली है और लोगों ने अपनी रुचि के काम के लिए ऋण लिये हैं।

उन्होंने कहा कि इस योजना के लाभार्थियों से उन्होंने 28 जनवरी, 2023 को भी बात की थी और तब से अब तक इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने

वाले लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई सरकार काम करती है तो उसको कभी सरकारी योजना कहा जाता है, कभी व्यवस्था परिवर्तन या कभी दायित्व की बात कही जाती है।

पहले की सरकारें नारा देती थी कि गरीबी हटाओ, लेकिन हमने नारा नहीं दिया, हमने तो उस हर गरीब की, जिसकी कोई मजबूरी या कठिनाई है, उसे समझ कर उसको दूर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा में भी 9 लाख सिलेंडर दिए हैं।

28 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाया है। इसी प्रकार से आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाते हुए हमने चिरायु योजना चलाई, ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक परिवार योजना में शामिल हो सकें। गरीब परिवारों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए मदद दी जा रही है। साथ ही स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 18 विभागों की 56 योजनाओं का चयन किया गया है।

इनके अलावा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भी इस योजना के साथ जोड़ा गया है। इन सभी विभागों और उनकी योजनाओं को https:@@parivarutthan-haryana-gov-in पोर्टल पर अपलोड किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति कभी भी और कहीं पर भी इनकी जानकारी हासिल कर सके।

उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर योजनाओं की जानकारी के अलावा, पात्रता व लाभ का विवरण भी दिया गया है। इसी पोर्टल पर पात्र व्यक्ति योजना के लिए आवेदन भी कर सकता है। उन्होंने अनुरोध किया कि जिन परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया है, वे अन्य परिवारों को भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश में लगभग

साप्ताहिक सूचना पत्र

55 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाये हैं, जिनके माध्यम से 5 लाख से अधिक महिलाएं अपने परिवार के लिए आय बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। एसएचजी द्वारा बनाये गए उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार ने शहरों में एक नई योजना सांझा बाजार के तहत 50–100 पोर्टा कैबिन बनाये हैं, ताकि बुकिंग के आधार एसएचजी अपने उत्पाद बेच सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार ने विदेश सहयोग विभाग के अंतर्गत ओवरसीज प्लेसमेंट सेल भी बनाया है।

इसके माध्यम से युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 25 दिसम्बर, 2022 से ऑटो मोड पर बीपीएल राशन कार्ड बनाने का काम शुरू किया है। जनवरी माह में लगभग साढ़े 12 लाख नये राशन कार्ड बनाये गए। प्रदेश में 35 लाख उन परिवारों को ऑनलाइन बी.पी.एल राशन कार्ड दिए गये हैं, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये तक है। परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक आय के मापदंड के आधार पर एएवाई / बीपीएल में कुछ नए परिवार जोड़े गए हैं। आयुष्मान चिरायु योजना में अब तक 8 लाख से अधिक लोगों का 920 करोड़ रुपये की लागत से हुआ मुफ्त इलाज।

उन्होंने कहा कि बी.पी.एल. परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए आयुष्मान–चिरायु योजना शुरू की गई है। आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उन परिवारों को शामिल किया गया है, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार रुपये से कम है। हमने बी.पी.एल. के लिए यह आय सीमा बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये वार्षिक की और पिछले दिनों 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को भी 1500 रुपये वार्षिक के मामूली अंशदान पर इस योजना में शामिल किया है। अब तक इस योजना में 86 लाख व्यक्तियों के आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाये जा चुके हैं।

फरीदाबाद जिला के विभिन्न विभागों में चल रहे 25 करोड़ रुपये विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक

(दिनांक 02.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज शनिवार को फरीदाबाद जिला में चल रही 25 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं की समीक्षा कर कहा कि पानी हमारे लिए बेशकीमती है और हमें उसकी बूंद–बूंद का सदुपयोग करना है। ऐसे में हमें सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांट (एसटीपी) के पानी के शोधन का स्तर इतना बेहतरीन करना है कि उसका बागवानी, शौचालयों सहित दैनिक जीवन के कार्यों में प्रयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमें साफ पानी सिर्फ पीने और नहाने के प्रयोग तक ही सीमित करना होगा। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री ने जी कहा कि भविष्य में विकसित होने वाले एचएसवीपी के सेक्टरों में पानी की दो पाईपलाईन बिछाने के निर्देश दिए गए

हैं। इनमें एक में पेयजल और दूसरी पाईपलाईन में सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांट से शोधित पानी की सप्लाई होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि फरीदाबाद में जितने भी रैनीवैल व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों पर काम चल रहा है, उन्हें समय पर पूरा करें। इनमें एफएमडीए की बसंतपुर में पेयजल सप्लाई स्कीम और मास्टर सीवरेज स्कीम योजना शामिल है। इसके अलावा, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) आधार पर बनने वाले आठ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी उन्होंने समीक्षा की।

उन्होंने स्मार्ट सिटी के बडख़ल झील फ्रंट व मैरिना डेवलेपमेंट, पुलिस लाईन से शेरशाह सूरी मार्ग तक तीन अतिरिक्त रोड निर्माण, आईटीआई से नीलम चौक रोड, राजा नाहर सिंह स्टेडियम, ओल्ड फरीदाबाद की डिस्पेंसरी व नगर निगम भवन के निर्माण की भी समीक्षा की। साथ ही उन्होंने एमसीएफ, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, एचवीपीएनएल व

वाईएमसीए के नए ब्लॉक निर्माण कार्यों की समीक्षा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद के लघु सचिवालय में छोटे बच्चों के लिए क्रैच सेंटर का उद्घाटन किया। इस क्रैच सेंटर को लघु सचिवालय में काम करने वाली महिला अधिकारियों–कर्मचारियों के छोटे बच्चों व कामकाज के लिए आने वाली महिलाओं के छोटे बच्चों के लिए तैयार किया गया है। इस क्रैच सेंटर में फिडिंग रूम, रेस्ट रूम, प्ले सेंटर, रीडिंग एरिया, आर्ट कार्नर, स्टडी एरिया, प्लेयिंग एरिया और एक्टिविटी एरिया बनाया गया है।